

भारत संघ और अन्य

बनाम

प्रबंधक मैसर्स जैन एंड एसोसिएट्स

6 फ़रवरी 2001

[एम बी शाह. & एस.एन. फुकन.]

मध्यस्थता अधिनियम, 1940:

धारा 17-निर्णय! और ऑर्डर IX नियम 13 सीपीसी के तहत डिक्री की प्रयोज्यता-पुरस्कार पर आपत्ति- सीमा की अवधि के भीतर दायर नहीं की गई- एकपक्षीय डिक्री पारित की गई और पुरस्कार को अदालत का नियम बना दिया गया आवेदन / या ऐसे एकपक्षीय डिक्री को अलग करने पर विचार नहीं किया गया आधार यह है कि धारा 17 के तहत निर्णय और डिक्री O के तहत एक पक्षीय डिक्री नहीं है। IX R. 13 सीपीसी हेल्ड की शुद्धतामध्यस्थता कार्यवाही में पक्षों को अभियोक्ता या प्रतिअभियोक्ता के रूप में वर्णित करने की प्रथा नहीं हो सकती है-लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि OIX R. 13 सी. पी. सी. उस मामले में लागू नहीं होता है जहां किसी निर्णय पर आपत्ति जताने वाला पक्ष S.17-For के तहत निर्णय सुनाता है, इस तरह की डिक्री एकतरफा डिक्री है-इसलिए, धारा 17 के तहत पारित निर्णय और डिक्री को अलग करने के लिए आवेदन पर विचार किया जा सकता है-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, O. IX R. 13.

धारा 30 और 33 धारा 30 और 33-अवार्ड-आपत्ति के तहत आवेदन--सीमा अवधि के भीतर दायर नहीं किया गया- एकपक्षीय डिक्री के तहत पारित धारा 17 के तहत डिक्री पारित होने के बाद भी इस तरह के आवेदन पर विचार किया जा सकता है

बशर्ते पर्याप्त कारण दिखाया गया हो-सीमा अधिनियम, 1963, धारा 5 और कला। जे 19 (ए) एससी।

शब्द और वाक्यांश:

"कार्यवाही "-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की खंड 141 के संदर्भ में।

"निर्णय का उच्चारण करें "-मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 17 के संदर्भ में।

मध्यस्थ ने अपीलार्थियों के खिलाफ एक निर्णय पारित किया और मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 30 और 33 के तहत कोई आपत्ति सीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची के अनुच्छेद 1। 9 (b) के तहत निर्धारित सीमा की अवधि के भीतर दायर नहीं की गई थी। इसलिए, उच्च न्यायालय ने न्यायालय का पुरस्कार नियम बनाया।

अपीलार्थियों ने पुरस्कार को रद्द करने और आवेदन दाखिल करने में देरी को माफ करने के लिए एक आवेदन दायर किया। उच्च न्यायालय ने डिक्री को पूरी तरह से इस आधार पर खारिज करने के लिए आवेदन को खारिज कर दिया कि अधिनियम की खंड 17 के संदर्भ में पारित निर्णय और डिक्री, जहां निर्णय देने और डिक्री पारित करने से पहले कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई थी, को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश IX नियम 13 के अर्थ के भीतर एक-पक्षीय डिक्री नहीं कहा जा सकता है। इसलिए यह अपील की गई है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

1. मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की खंड 41 में कोई संदेह नहीं है कि ऐसी कार्यवाही में जहां मध्यस्थ द्वारा प्रस्तुत किए गए निर्णय के आधार पर डिक्री पारित

करने के लिए आवेदन दायर किया जाता है, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधान लागू होते हैं और ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें आदेश IX का संचालन शामिल न हो। इसी तरह, सी. पी. सी. की खंड 141 को ध्यान में रखते हुए, संहिता में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए जहां तक इसे सिविल अधिकार क्षेत्र के न्यायालय में सभी कार्यवाहियों पर लागू किया जा सकता है। इसलिए, न्यायालय का अधिनिर्णय नियम बनाने के लिए शुरू की गई कार्यवाही में, आदेश IX नियम 13 सहित सी. पी. सी. के प्रावधान लागू होंगे। [894-ए-बी]

2.1 अधिनियम की खंड 41 के तहत सी. पी. सी. के प्रावधान न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता कार्यवाही और अधिनियम के तहत अपीलों पर लागू किए जाते हैं। मध्यस्थता कार्यवाही में, मुकदमा दायर करने का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि पुरस्कार के संदर्भ में डिक्री पारित करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। इसी तरह, सी. पी. सी. की खंड 141 सिविल अधिकार क्षेत्र के किसी भी न्यायालय में मुकदमा के अलावा अन्य कार्यवाहियों पर भी विचार करती है और यह प्रावधान करती है कि मुकदमा के संबंध में संहिता में प्रदान की गई प्रक्रिया का पालन किया जाएगा जहां तक इसे लागू किया जा सकता है। ऐसी कार्यवाही में, पक्षकारों को अभियोक्ता या प्रतिअभियोक्ता के रूप में वर्णित करने की कोई प्रथा या प्रक्रिया नहीं हो सकती है। इसलिए, मध्यस्थता कार्यवाही में भले ही मुकदमा दायर नहीं किया गया हो, सी. पी. सी. में प्रदान की गई प्रक्रिया लागू होती है और यह मानने का कोई कारण नहीं है कि चूंकि किसी भी पक्ष को अभियोक्ता या प्रतिअभियोक्ता के रूप में वर्णित नहीं किया गया है, इसलिए आदेश IX लागू नहीं होगा। [899-सी-ई]

2.2. सी. पी. सी. के प्रावधान विशेष रूप से लागू किए गए हैं और यह मानने का कोई कारण नहीं है कि आदेश IX नियम 13 उस मामले में लागू नहीं होगा जहां

निर्णय पर आपत्ति करने वाले पक्ष द्वारा दिए गए आपत्ति आवेदन की अनुपस्थिति में अधिनियम की खंड 17 के तहत निर्णय सुनाया जाता है। सभी उद्देश्यों के लिए ऐसी डिफ्री पुरस्कार पर आपत्ति करने वाले पक्ष के लिए एक्स-पी. ए. आर. टी. है। सी. पी. सी. के तहत एकतरफा डिफ्री का कोई तकनीकी अर्थ नहीं है। [900-डी]

बलराज तनेजा बनाम सुनी/मदन, [1999 [8 एस. सी. सी. 396; केसोरम कॉटन मिल्स लिमिटेड, ए. आई. आर. 39 (1952) कैल 10; ए. पी. सरकार। वी. बक्टचाला बलैया, ए. आई. आर. (1985) ए. पी. 52 और राम चंद्र बनाम जमना शंकर, ए. आई. आर. (1962) राज। 12 वेबस्टर्स कॉम्प्रिहेंसिव डिक्शनरी इंटरनेशनल एडिशन, वॉल्यूम। 1 (1984) का उल्लेख किया गया है।

3. खंड 17 के तहत एक डिफ्री पारित होने के बाद भी, अधिनियम की खंड 30 और 33 के तहत एक आवेदन पर विचार किया जा सकता है बशर्ते पर्याप्त कारण स्थापित हो। दोनों ही मामलों में आवेदन की अस्वीकृति पुरस्कार को रद्द करने से इनकार करना होगा। यदि ऐसा आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया जाता है कि इसमें देरी हुई है और सीमा अधिनियम, 1963 की खंड 5 के तहत कोई पर्याप्त कारण नहीं बताया गया है, तो यह अधिनियम की खंड 39 (1) (6) के तहत एक अपील योग्य आदेश होगा। [902-बी; 901-बी]

एस्सार कंस्ट्रक्शंस बनाम एन. पी. राम कृष्ण रेड्डी, [2000] 6 एस. सी. सी. 94, पर भरोसा किया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : दीवानी याचिका सं 1059/2001।

पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय के A.P.O.T. संख्या 858/1998 में दिनांकित 7.10.99 के निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थियों की ओर से मुकुल रोहतगी, बी. सुनीता राव, सुश्री पारुल मित्तल और सुश्री सुषमा सूरी।

प्रत्यर्थी के लिए अशोक एच. देसाई, डी. ए. दवे, सैयद अली अहमद, सैयद तनवीर अहमद, गिरधर जी. उपाध्याय, विकास बंसल और आर. डी. उपाध्याय।

न्यायालय का निर्णय शाह, जे. टी.जे द्वारा दिया गया था

अनुमति दी गई इस अपील में शामिल प्रश्न यह है कि क्या प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश IX नियम 13 के लिए (के लिए) संक्षेप में सीपीसी) या उसके सिद्धांतों के रूप में जाना जाता है ऐसे मामले में लागू होते हैं जहां धारा 33 के तहत आपत्तियां होती हैं मध्यस्थता अधिनियम, 1940 (संक्षेप में इसे कहा जाता है अधिनियम) दाखिल नहीं किये जाते तथा एक पक्षीय डिक्री पारित कर दी जाती है पुरस्कार को आधार बनाकर न्यायालय के समक्ष दायर किया गया न्यायालय का पुरस्कार नियम. हाई कोर्ट आ गया है निष्कर्ष कि आदेश IX नियम 13 सीपीसी लागू नहीं है ऐसे मामले।

तर्कों की सराहना करने से पहले, हम इसका संदर्भ लेंगे शामिल प्रश्न से संबंधित कुछ तारीखें। दोनों वर्तमान अपील के पक्षकारों के बीच विवाद चल रहा था दो लेन सड़क पुल के डिजाइन एवं निर्माण का कार्य (दोनों उप-संरचना और सुपर संरचना) फीडर नहर के पार R.D.16.5 पर (शेष कार्य)। 1993 के एक विशेष सूट नंबर 31 में वर्तमान प्रतिवादी, कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा दायर किया गया अपने आदेश दिनांक 25.6.1993 द्वारा नियुक्ति का निर्देश दिया उनके विवादों को निपटाने के लिए मध्यस्थ। मध्यस्थ पारित हो गया यहां अपीलकर्ताओं के खिलाफ दिनांक 28.12.1996 को एक पुरस्कार दिया गया जो 6.3.1997 को उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था। सूचना आपत्तियां दाखिल करने के लिए अपीलकर्ताओं द्वारा प्राप्त किया गया था

21.03.1997. आपत्तियां दाखिल करने के लिए 30 दिन का समय 20.4.1997 को समाप्त हो गया, जो रविवार था और इसलिए, तिथि 21.4.1997 तक बढ़ा दी गई। मामला रखा गया 28.4.1997 को न्यायालय के समक्ष और उस दिन न्यायालय के समक्ष के विद्वान अधिवक्ता की मौखिक प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया अपीलकर्ताओं का कहना है कि चूंकि धाराओं के तहत आपत्ति आवेदन है अधिनियम के 30 और 33 की तैयारी चल रही थी, फाइल करने का समय आ गया है ऐसा आवेदन मंजूर किया जाए. पुरस्कार का नियम बनाया गया उसी दिन कोर्ट. 5.5.1997 को, अपीलकर्ताओं ने एक दायर किया एक पक्षीय डिक्री को रद्द करने के लिए आवेदन और भी प्रस्तुत किया कि धारा 30 के तहत आवेदन तैयार था। मैं उक्त आवेदन, पुरस्कार को रद्द करने का आधार और आवेदन दाखिल करने में हुई देरी को माफ करने के लिए थे उल्लिखित। इसके बाद, धारा 33 के तहत एक और आवेदन इस पुरस्कार के खिलाफ आपत्तियां उठाने वाले अधिनियम के भी थे 16.5.1997 को दायर किया गया। विद्वान न्यायाधीश ने दिनांक आदेश द्वारा 25.9.1998 ने उक्त आवेदन खारिज कर दिया।

व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने डिवीजन बेंच का रुख किया अपील दायर करके. डिवीजन बेंच के मद्देनजर परस्पर विरोधी निर्णयों में यह प्रश्न संदर्भित था कि क्या मध्यस्थता पुरस्कार के संदर्भ में डिक्री पारित की गई, जहां नहीं आपत्ति तिथि से 30 दिन के भीतर दाखिल की गई है अधिनियम के संदर्भ में पुरस्कार दाखिल करना एक होगा आदेश IX नियम 13 के अर्थ में एकपक्षीय डिक्री पूर्ण पीठ को सी.पी.सी.? निर्णय एवं आदेश द्वारा पूर्ण पीठ दिनांक 7.10.1999 ने यह कहकर अपील खारिज कर दी कि:-

हमारी राय है कि (1) के संदर्भ में पारित डिक्री अधिनियम की धारा 17 जहां कोई आपत्ति दायर नहीं की जा सकती इसे एक पक्षीय डिक्री कहा गया; (2) के लिए एक आवेदन सीमा की धारा 5 के संदर्भ में देरी की माफ़ी आपत्ति दाखिल करने के लिए अधिनियम इन दोनों में से किसी एक के अंतर्गत लागू हो सकता है अधिनियम की धारा 30 या 33 या दोनों; (3) यथा क्षण मामले में ऐसा कोई आवेदन दायर नहीं किया गया है, का सवाल है डिक्री को रद्द करने का प्रश्न नहीं उठता; (4) एक आवेदन धारा 17 के संदर्भ में पारित डिक्री को रद्द करने के लिए अधिनियम केवल उसी मामले में कायम रखने योग्य है जहां डिक्री हो पूर्व निर्धारित शर्तों की अनदेखी करके पारित किया गया उसमें नीचे.

परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय ने आवेदन खारिज कर दिया केवल इस आधार पर डिक्री को रद्द करने के लिए अधिनियम की धारा 17 के संदर्भ में पारित निर्णय और डिक्री जहां फैसला सुनाने से पहले कोई आपत्ति दाखिल नहीं की जाती और डिक्री पारित करना एकपक्षीय नहीं कहा जा सकता हुक्मनामा। इसमें उस फैसले और आदेश को चुनौती दी गयी है निवेदन।

उपरोक्त प्रश्न पर निर्णय लिया जाना आवश्यक है अधिनियम की धारा 41 के आधार पर, जो यह प्रावधान करता है सीपीसी के प्रावधान सभी कार्यवाहियों पर लागू होते हैं अधिनियम के तहत न्यायालय के समक्ष। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:-

41. न्यायालय की प्रक्रिया एवं शक्तियाँ। के प्रावधानों के अधीन यह अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियम

(ए) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधान, न्यायालय के समक्ष सभी कार्यवाहियों और सभी पर लागू होगा इस अधिनियम के तहत अपील; और

(बी) न्यायालय के पास, के प्रयोजन के लिए और में होगा के संबंध में, मध्यस्थता कार्यवाही, की एक ही शक्ति इसमें निर्धारित किसी भी मामले के संबंध में आदेश देना दूसरी अनुसूची जैसा कि इसमें और इसके प्रयोजन के लिए है न्यायालय के समक्ष किसी भी कार्यवाही के संबंध में:

बशर्ते कि खंड (बी) में कुछ भी नहीं लिया जाएगा किसी भी शक्ति पर पूर्वाग्रह जो किसी मध्यस्थ में निहित हो सकती है इनमें से किसी के संबंध में आदेश देने के लिए अंपायर मायने रखता है.

उपरोक्त धारा को भी संदर्भ में पढ़ा जाना आवश्यक है सीपीसी की धारा 141, जो इस प्रकार है:-

"141. विविध कार्यवाही.प्रदत्त प्रक्रिया मुकदमों के संबंध में इस संहिता का जहां तक पालन किया जाएगा इसे किसी भी अदालत की सभी कार्यवाहियों में लागू किया जा सकता है नागरिक क्षेत्राधिकार का.

[स्पष्टीकरण। इस खंड में, अभिव्यक्ति कार्यवाही में आदेश IX के तहत कार्यवाही शामिल है, लेकिन शामिल है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कोई भी कार्यवाही शामिल नहीं है संविधान]

अधिनियम की धारा 41 इसमें कोई संदेह नहीं है कि कार्यवाही जहां पारित करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया है द्वारा प्रस्तुत पुरस्कार के आधार पर डिग्री

मध्यस्थ, सीपीसी के प्रावधान लागू हैं और ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो आदेश IX के संचालन को बाहर करता हो। इसी प्रकार सीपीसी की धारा 141 के दृष्टिगत कार्यवाही संहिता में निर्धारित प्रावधानों का यथासंभव पालन किया जाना चाहिए सिविल न्यायालय की सभी कार्यवाहियों पर लागू किया गया क्षेत्राधिकार। इसलिए, के लिए शुरू की गई कार्यवाही में न्यायालय के पुरस्कार नियम बनाना, सीपीसी के प्रावधान आदेश IX सहित नियम 13 लागू होगा। के अनुसार धारा 141 का स्पष्टीकरण, अभिव्यक्ति कार्यवाही आदेश IX सीपीसी के तहत कार्यवाही शामिल है।

अन्य प्रावधान जिन्हें ध्यान में रखा जाना आवश्यक है परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 पर विचार किया जा रहा है। जो अन्य बातों के साथ-साथ निर्धारित अवधि के विस्तार का प्रावधान करता है सिविल में आवेदन करने की सीमा कार्यवाही, यदि आवेदक न्यायालय को संतुष्ट करता है कि वह ऐसे में आवेदन न करने का पर्याप्त कारण था अवधि। आपत्ति आवेदन दाखिल करने के प्रयोजन हेतु न्यायालय के समक्ष, प्रासंगिक प्रावधान अनुच्छेद 119 है सीमा अधिनियम, 1963, जो अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करता है में पुरस्कार दाखिल करने के लिए सीमा अवधि 30 दिन है न्यायालय द्वारा नोटिस तामील किये जाने की तिथि से पुरस्कार और पुरस्कार को अलग रखने या प्राप्त करने के लिए 30 दिन की तिथि से पुनर्विचार हेतु प्रेषित पुरस्कार पुरस्कार दाखिल करने की सूचना की सेवा। उसकी आवश्यकता है पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर इस पर कोई और चर्चा नहीं की गई, यदि सेटिंग के लिए आवेदन दाखिल करने में कोई देरी हो रही है पुरस्कार के अलावा, इसे माफ किया जा सकता है। हम आगे भी करेंगे धारा 15, 16, , 30 और 33 अधिनियम के जो निम्नानुसार पढ़ें:-

“15. पुरस्कार को संशोधित करने की न्यायालय की शक्ति। (1) न्यायालय कर सकता है आदेश द्वारा किसी पुरस्कार को संशोधित या सही करना

(ए) जहां ऐसा प्रतीत होता है कि पुरस्कार का एक हिस्सा ए पर है मामला मध्यस्थता के लिए नहीं भेजा गया है और ऐसा हिस्सा हो सकता है दूसरे भाग से अलग हो जाता है और प्रभावित नहीं करता है संदर्भित मामले पर निर्णय; या

(बी) जहां पुरस्कार स्वरूप में अपूर्ण है, या शामिल है कोई भी स्पष्ट त्रुटि जिसे प्रभावित किए बिना संशोधित किया जा सकता है ऐसा निर्णय; या

(सी) जहां पुरस्कार में लिपिकीय गलती हो या आकस्मिक चूक या चूक से उत्पन्न त्रुटि।

(महत्व जोड़ें)

16. पुरस्कार माफ करने की शक्ति.(1) न्यायालय समय-समय पर कर सकता है पुरस्कार या संदर्भित किसी भी मामले को समय पर प्रेषित करने के लिए पुनर्विचार के लिए मध्यस्थों या अंपायर को मध्यस्थता ऐसी शर्तों पर जो वह उचित समझे

(ए) जहां पुरस्कार ने इनमें से किसी को भी अनिर्धारित छोड़ दिया है मध्यस्थता के लिए संदर्भित मामले, या जहां यह कोई भी निर्धारित करता है मामला मध्यस्थता के लिए नहीं भेजा गया है और ऐसा

मामला नहीं हो सकता है मामलों के निर्धारण को प्रभावित किए बिना अलग कर दिया गया निर्दिष्ट; या

(बी) जहां पुरस्कार इतना अनिश्चित है कि अक्षम है निष्पादन का; या

(सी) जहां पुरस्कार की वैधता पर आपत्ति है यह प्रथम दृष्टया स्पष्ट है।

(2) जहां एक पुरस्कार उप-धारा (1) के तहत प्रेषित किया जाता है न्यायालय वह समय तय करेगा जिसके भीतर मध्यस्थ या अंपायर अपना निर्णय न्यायालय को प्रस्तुत करेगा:

बशर्ते कि इस प्रकार निर्धारित किसी भी समय को बढ़ाया जा सके न्यायालय के आगामी आदेश. (3) के तहत दिया गया एक पुरस्कार की विफलता पर उपधारा (1) शून्य हो जायेगी मध्यस्थ या अंपायर इस पर पुनर्विचार करें और अपनी बात प्रस्तुत करें तय समय के अंदर फैसला.

(महत्व जोड़ें)

17. पुरस्कार के संदर्भ में निर्णय। जहां न्यायालय को कोई नहीं दिखता पुरस्कार या संदर्भित किसी भी मामले को माफ करने का कारण पुनर्विचार के लिए मध्यस्थता या पुरस्कार को रद्द करना, न्यायालय, आवेदन करने के समय के बाद पुरस्कार की अवधि समाप्त हो गई है, या ऐसा आवेदन रद्द कर दिया गया है बनाया गया है, इससे इनकार करने के बाद निर्णय सुनाने के लिए आगे बढ़ें पुरस्कार के अनुसार, और इस प्रकार सुनाए गए निर्णय के अनुसार एक डिक्री का पालन किया जाएगा, और उसकी ओर से कोई अपील नहीं की

जाएगी डिफ्री, सिवाय इस आधार पर कि यह अधिक है या नहीं अन्यथा पुरस्कार के अनुरूप.

30. पुरस्कार रद्द करने का आधार. कोई पुरस्कार नहीं होगा निम्नलिखित में से एक या अधिक आधारों को छोड़कर अलग रखा जाएगा, अर्थात्:

(ए) कि एक मध्यस्थ या अंपायर ने कदाचार किया है स्वयं या कार्यवाही;

(बी) कि एक पुरस्कार जारी होने के बाद बनाया गया है मध्यस्थता को अधिक्रमण करने वाला या उसके बाद न्यायालय द्वारा आदेश धारा के तहत मध्यस्थता कार्यवाही अमान्य हो गई है 35;

(सी) कि कोई पुरस्कार अनुचित तरीके से प्राप्त किया गया है या है अन्यथा अमान्य.

33. मध्यस्थता समझौते या पुरस्कार का विरोध किया जाना आवेदन। मध्यस्थता समझौते का कोई भी पक्ष या कोई भी उसके अधीन दावा करने वाला व्यक्ति चुनौती देने की इच्छा रखता है मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व या वैधता या पुरस्कार या प्रभाव का निर्धारण दोनों में से किसी एक पर लागू होगा न्यायालय को और न्यायालय इस प्रश्न पर निर्णय करेगा शपथ पत्र:

बशर्ते कि जहां न्यायालय इसे उचित समझे और समीचीन, यह आवेदन को सुनवाई के लिए निर्धारित कर सकता है अन्य साक्ष्य भी,

और यह ऐसे आदेश पारित कर सकता है खोज और विवरण जैसा कि यह एक सूट में हो सकता है।

उपरोक्त धाराओं को ध्यान में रखते हुए, यह कहा जा सकता है वह--
(ए) किसी पुरस्कार की प्राप्ति के बाद, न्यायालय स्वतः संज्ञान ले सकता है इस आधार पर न्यायालय के पुरस्कार नियम बनाने से इनकार करें

(i) पुरस्कार का एक हिस्सा ऐसे मामले पर है जिसका उल्लेख नहीं किया गया है मध्यस्थता करना; और (ii) पुरस्कार का स्वरूप अपूर्ण है या कोई स्पष्ट त्रुटि है. न्यायालय भी माफ़ कर सकता है मामले में मध्यस्थ को पुरस्कार (i) जहां पुरस्कार समाप्त हो गया है मध्यस्थता के लिए भेजा गया कोई भी मामला अनिश्चित; या (ii) जहां इसने संदर्भित नहीं किए गए किसी भी मामले का निर्धारण किया है मध्यस्थता करना; या (iii) पुरस्कार इतना अनिश्चित है निष्पादन में असमर्थ; या (iv) इसके प्रथम पक्ष पर है गैरकानूनी। यह भी कोष्ठक खंड के अंतर्गत प्रदान किया गया है धारा 17 जो प्रावधान करती है कि जहां न्यायालय को कोई कारण नहीं दिखता पुरस्कार या संदर्भित किसी भी मामले को माफ़ करना पुनर्विचार के लिए मध्यस्थता या पुरस्कार को रद्द करना, न्यायालय निर्णय सुनाने के लिए आगे बढ़ेगा इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसे मामले में जहां आपत्तियां हैं धारा 30 या 33 दायर नहीं किए गए हैं, न्यायालय पारित करने के लिए बाध्य है पुरस्कार के संदर्भ में डिक्री.

(b) सीमा अधिनियम की धारा 5 विवेकाधिकार देती है के तहत आवेदन दाखिल करने का समय बढ़ाने के लिए कोर्ट धर्मा धारा 30 या 33 पुरस्कार पर आपत्तियां उठाना।

(सी) आदेश IX नियम 13 सहित सिविल प्रक्रिया संहिता उत्पादन द्वारा शुरू की गई कार्यवाही पर लागू होता है डिक्री पारित करने के लिए न्यायालय के समक्ष पुरस्कार।

(डी) के तहत पुरस्कार को संशोधित करने की न्यायालय की शक्ति धारा 15 या निर्णय को मध्यस्थ को सौंपना धारा 16 के तहत पुनर्विचार भिन्न होता है के तहत पुरस्कार को रद्द करने का न्यायालय का अधिकार क्षेत्र धारा 30 या मध्यस्थता की वैधता निर्धारित करने के लिए धारा 33 के तहत समझौता या पुरस्कार।

फैसला सुनाने से पहले कोर्ट ने नतीजा निकाला है निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अपना दिमाग लगाना होगा कि क्या वहां पुरस्कार को संशोधित करने या हटाने का कोई कारण है। आगे वाक्यांश उच्चारण निर्णय स्वयं ही न्यायिक संकेत देगा पर पहुंचने के लिए तर्कपूर्ण आदेश द्वारा निर्धारण निष्कर्ष यह कि पुरस्कार के संदर्भ में डिक्री पारित की जाए। मैं से एक वेबस्टर्स में जजमेंट शब्द को दिया गया अर्थ व्यापक शब्दकोश [अंतर्राष्ट्रीय संस्करण, वॉल्यूम। मैं (1984)] इस प्रकार पढ़ता है: न्याय करने का परिणाम; निर्णय या निष्कर्ष पर पहुंचे, जैसे कि विचार के बाद या विचार-विमर्श. इसके अलावा, आदेश XX नियम 4(2) सी.पी.सी. मामले में यह प्रावधान करता है कि निर्णय में एक संक्षिप्त विवरण होगा मामले की स्थिति, निर्धारण के बिंदु, उस पर निर्णय, और ऐसे निर्णय के कारण। यह इसके विपरीत है न बोलने वाले आदेश की घोषणा ।

अधिनियम की धारा 17, कुछ हद तक, के समान है आदेश VIII नियम 5 और/या नियम 10 सीपीसी के प्रावधान। आदेश VIII वह प्रक्रिया प्रदान करता है जहाँ लिखित कथन द्वारा प्रतिवादी दायर नहीं किया गया है. आदेश VIII नियम 5(2)(4) प्रदान करता है कि जहां प्रतिवादी ने याचिका दायर नहीं की है, वहां यह किया जाएगा न्यायालय के लिए आधार पर निर्णय सुनाना वैध होगा वादपत्र में निहित तथ्यों के बारे में और फैसला सुनाने के बाद निर्णय के अनुसार एक डिक्री तैयार की जानी आवश्यक है ऐसे फैसले के साथ. आदेश VIII नियम 10 के तहत जहां कोई हो वह पक्ष जिससे नियम 1 के तहत एक लिखित बयान की आवश्यकता है या नियम 9 उसे समय के भीतर प्रस्तुत करने में विफल रहता है न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई या तय की गई, न्यायालय सुनाएगा उसके विरुद्ध निर्णय दे या उसके संबंध में ऐसा आदेश दे जैसा वह उचित समझे वैसा ही और ऐसे उच्चारण पर निर्णय एक डिक्री तैयार की जाएगी. यह नियम एक देता है या तो फैसला सुनाने का विवेक न्यायालय को है प्रतिवादी के विरुद्ध या उसके संबंध में ऐसा आदेश करें जैसा उचित समझे वैसा सूट करें। आदेश VIII की व्याख्या करते समय, यह कोर्ट में बलराज तनेजा और amp; अन्य बनाम सुनील मदान & एक और [(1999) 8 एससीसी 396] का मानना है कि यह केवल इसलिए लिखा गया है बयान दाखिल नहीं किया गया है, अदालत को पारित करने के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए आँख मूँद कर निर्णय लिया और इस प्रकार देखा:-

न्यायालय को स्वीकारोक्ति पर आँख मूँदकर कार्य नहीं करना चाहिए प्रतिवादी द्वारा अपने लिखित बयान में दिया गया एक तथ्य क्या अदालत को केवल आंख मूँदकर फैसला सुनाना चाहिए? क्योंकि की ओर से लिखित बयान दाखिल नहीं किया गया है प्रतिवादी वादी द्वारा निर्धारित तथ्यों का पता लगा रहा है अदालत में दायर की गई याचिका. एक मामले में, विशेष रूप से जहां ए प्रतिवादी द्वारा लिखित

बयान दाखिल नहीं किया गया है कोर्ट को आदेश के तहत कार्यवाही में थोड़ा सतर्क रहना चाहिए 8 नियम 10 सीपीसी। के खिलाफ फैसला सुनाने से पहले प्रतिवादी को यह अवश्य देखना चाहिए कि भले ही तथ्य सामने आएँ वादपत्र में इसे एक निर्णय के रूप में स्वीकार किया गया माना जाता है संभवतः बिना वादी के पक्ष में पारित किया जा सकता है उनसे वाद-पत्र में उल्लिखित किसी भी तथ्य को साबित करने की अपेक्षा की गई। यह यह केवल अदालत की संतुष्टि का मामला है और इसलिए इस बात से संतुष्ट होने पर कि इसमें कोई तथ्य नहीं है जिसकी आवश्यकता है डीमंड प्रवेश के आधार पर साबित किया जा सकता है, अदालत कर सकती है जिस प्रतिवादी के पास है उसके विरुद्ध आसानी से निर्णय पारित करें लिखित बयान दाखिल नहीं किया.

इसी तरह, जब न्यायालय को बिना आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है अधिनियम की धारा 30 या 33 के अंतर्गत आपत्ति आवेदन, यह बिना विचार किये निर्णय नहीं सुना सकते अधिनियम की धारा 15 और 16 के प्रावधान, जो प्रदान करते हैं, जैसा कि ऊपर कहा गया है, किसी भी पुरस्कार में संशोधन या सुधार के लिए या इसे पुनः विचार के लिए मध्यस्थ के पास भेजने के लिए इस आधार पर कि (i) कानून की कोई त्रुटि स्पष्ट है पुरस्कार का चेहरा, (ii) पुरस्कार होने में असमर्थ है निष्पादित, (iii) पुरस्कार ने इनमें से किसी को भी अनिर्धारित छोड़ दिया है मध्यस्थता के लिए संदर्भित मामले, (iv) का एक हिस्सा पुरस्कार ऐसे मामले पर है जो मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं है और (v) पुरस्कार में कोई स्पष्ट त्रुटि है। का क्षेत्राधिकार न्यायालय निर्णय सुनाना अपनी शक्ति के प्रयोग पर निर्भर करता है पुरस्कार को संशोधित करना या हटाना।

इसके अलावा, उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ पहुंची निष्कर्ष कि डिक्री धारा 17 के संदर्भ में पारित हुई ऐसा अधिनियम जहां कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गई है, नहीं कहा जा सकता एक पक्षीय डिक्री क्योंकि (1) भले ही दोनों पक्ष हों अनुपस्थित होने पर न्यायालय का कर्तव्य है कि वह इसके विपरीत डिक्री पारित करे सीपीसी के आदेश IX का प्रावधान; (2) न्यायालय पारित करता है पुरस्कार के आधार पर डिक्री, जो बोलने लायक नहीं हो सकती है इससे पहले किसी भी पक्ष को अपना सबूत दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है इसके दावे या बचाव का सम्मान; और (3) एक सूट में है एक वादी और प्रतिवादी और आदेश IX उनसे संबंधित है। जैसा इसके विरुद्ध, पुरस्कार के आधार पर कार्यवाही में, सख्ती से किसी पुरस्कार का कोई भी पक्ष वादी या प्रतिवादी और दोनों नहीं है उनमें से वे न्यायालय से निर्णय सुनाने के लिए कहने के हकदार हैं पुरस्कार के अनुसार. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, भेद उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर बनाया गया कि भले ही दोनों पक्ष अनुपस्थित हैं, न्यायालय का कर्तव्य है कि वह डिक्री पारित करे आदेश IX के प्रावधानों के विपरीत सीपीसी निराधार है। पहले निर्णय सुनाते समय न्यायालय को विचार करना आवश्यक है और अधिनियम की धारा 15 और 16 के प्रावधानों का पालन करें। इसके अलावा, एक बार यह माना जाता है कि सीपीसी के प्रावधान हैं लागू होता है और यदि वह पक्ष जो डिक्री चाहता है, के संदर्भ में पुरस्कार अनुपस्थित है, न्यायालय डिक्री पारित करने से इंकार कर सकता है। के लिए यही कारण, न्यायालय द्वारा दिया गया दूसरा आधार भी है समर्थन नहीं किया जा सकता क्योंकि न बोलने की स्थिति में भी पुरस्कार देने के लिए न्यायालय को धारा 15 के अधिदेश का पालन करना आवश्यक है और फैसला सुनाने से पहले अधिनियम के 16 । यह मानने का तीसरा आधार कि पुरस्कार के मामले में कोई नहीं है वादी या प्रतिवादी, इसलिए, आदेश IX सीपीसी जो संबंधित है वादी या प्रतिवादी की अनुपस्थिति में ऐसा नहीं होगा लागू भी बरकरार नहीं रखा जा सकता क्योंकि धारा 41 के

तहत अधिनियम में सीपीसी के प्रावधानों को लागू किया गया है अदालत के समक्ष और अपीलों के लिए मध्यस्थता की कार्यवाही अधिनियम के तहत. मध्यस्थता कार्यवाही में, कोई नहीं है पुरस्कार के रूप में मुकदमा दायर किए जाने का प्रश्न प्रस्तुत किया गया है पुरस्कार के संदर्भ में डिक्री पारित करना। इसी प्रकार, धारा सीपीसी की धारा 141 मुकदमे के अलावा अन्य कार्यवाही पर भी विचार करती है सिविल क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय में और वह प्रदान करता है मुकदमे के संबंध में संहिता में प्रदान की गई प्रक्रिया होगी जहां तक इसे लागू किया जा सके, इसका पालन किया जाए। ऐसे में कार्यवाही, अभ्यास या प्रक्रिया नहीं हो सकती है पार्टियों को वादी या प्रतिवादी के रूप में वर्णित करना। इसलिए, में मुकदमा दायर न होने पर भी मध्यस्थता की कार्यवाही, सीपीसी में प्रदान की गई प्रक्रिया लागू है और नहीं है ऐसा मानने का कारण यह है कि किसी भी पक्ष को वादी या के रूप में वर्णित नहीं किया गया है प्रतिवादी, आदेश IX लागू नहीं होगा। भले ही वादी या प्रतिवादी का नामकरण होना आवश्यक है उस पक्ष को ध्यान में रखा जाता है जो डिक्री चाहता है पुरस्कार की शर्तों में वादी और पक्ष दोनों को माना जा सकता है ऐसे पुरस्कार की वस्तुओं को प्रतिवादी के रूप में माना जा सकता है। यदि तर्क यह है कि सीपीसी लागू करने के लिए मुकदमा होना चाहिए, वादी, वादी, प्रतिवादी या लिखित बयान है स्वीकार किया गया, अधिनियम की धारा 41 के प्रावधान और सीपीसी की धारा 141 निष्प्रभावी होगी.

इस स्तर पर, हम कुछ निर्णयों का उल्लेख करेंगे, जो उच्च न्यायालय द्वारा संदर्भित किया गया था। कोर्ट ने संदर्भित किया गणेशमल भवरलाल बनाम केसोराम कॉटन मिल्स लिमिटेड। [एआईआर (39) 1952 कलकत्ता 10], जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश ने अवलोकन किया कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 43 के बावजूद और सीपीसी की धारा 141 सख्त रूप से आदेश IX का प्रावधान है नियम 13 किसी को रद्द करने की कार्यवाही पर लागू नहीं होता है धारा 17 के अंतर्गत पारित एक पक्षीय डिक्री

लेकिन सिद्धांत आदेश IX नियम 13 सीपीसी का पालन किया जाना चाहिए और निर्णय दिया जाना चाहिए धारा 17 के तहत पारित डिक्री को रद्द किया जा सकता है जहां ऐसी डिक्री बिना विधिवत सूचना दिए पारित की गई पुरस्कार दाखिल करना या आवेदन करने के लिए समय दिए बिना पुरस्कार को समाप्त करने के लिए अलग रखा जाए। आंध्र प्रदेश सरकार में वी. बैक्टचाला बलैया [एआईआर 1985 ए.पी. 52], उच्च न्यायालय एक ही प्रभाव के विभिन्न निर्णयों पर विचार किया गया और आयोजित किया गया आदेश IX नियम 13 का प्रावधान लागू नहीं होगा मध्यस्थता अधिनियम की धारा 17 के तहत पारित डिक्री मध्यस्थ द्वारा न्यायालय में दायर किए गए पुरस्कार की शर्तें इसे एकपक्षीय नहीं माना जा सकता, खासकर जब कोई याचिका हो अधिनियम की धारा 30 के तहत पुरस्कार को रद्द करने का आदेश दिया गया था नोटिस की सेवा की तारीख से 30 दिनों के भीतर दाखिल नहीं किया गया न्यायालय में पुरस्कार के आवेदन के संबंध में। के मामले में राम चंद्र बनाम जमना शंकर, [AIR 1962 राज. 12], द कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले का पालन किया गणेशमल्स केस (सुप्रा) और उस सिद्धांत का अवलोकन किया आदेश IX नियम 13 का पालन किया जाना चाहिए और किसी भी स्थिति में न्यायालय के पास अन्याय को सुधारने और स्थापित करने की अंतर्निहित शक्ति है निर्णय और डिक्री को बिना किसी सूचना के एकपक्षीय पारित कर दिया गया इच्छुक पार्टी को।

हमारे विचार में, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, सीपीसी के प्रावधान विशेष रूप से लागू किए गए हैं और इसका कोई कारण नहीं है मान लें कि आदेश IX नियम 13 मामले में लागू नहीं होगा जहां अधिनियम की धारा 17 के तहत निर्णय सुनाया जाता है पार्टी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति आवेदन का अभाव पुरस्कार पर आपत्ति ऐसी डिक्री सभी प्रयोजनों के लिए है पुरस्कार पर आपत्ति जताने वाली पार्टी के लिए एकपक्षीय। सी.पी.सी. के तहत एक पक्षीय डिक्री का कोई तकनीकी अर्थ नहीं है। आदेश IX नियम

6 सीपीसी प्रदान करता है कि वादी कहां उपस्थित होता है और जब मुकदमा बुलाया जाता है तो प्रतिवादी उपस्थित नहीं होता है सुनवाई, तो यदि यह साबित हो जाए कि समन की तामील विधिवत की गई थी, न्यायालय यह आदेश दे सकता है कि मुकदमे की एकपक्षीय सुनवाई की जाए। ऐसा आदेश पारित करने के बाद यदि कोई डिक्री एकपक्षीय पारित की जाती है प्रतिवादी के विरुद्ध, नियम 13 के तहत, न्यायालय को शक्ति है यदि वह संतुष्ट है कि सम्मन विधिवत नहीं था तो इसे अलग रख दें सेवा प्रदान की गई या प्रतिवादी को किसी पर्याप्त द्वारा रोका गया जब मुकदमा बुलाया गया था तब उपस्थित होने का कारण श्रवण. इसी तरह, अगर पार्टी पुरस्कार पर आपत्ति जताती है न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि पर्याप्त कारणों से आपत्ति है निर्धारित समय के भीतर आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया, न्यायालय ऐसी डिक्री को रद्द करने की शक्ति है। इसलिए, यदि पुरस्कार को रद्द करने के लिए आवेदन इससे परे दायर किया गया है विलंब को माफ करने के लिए निर्धारित समय और पर्याप्त कारण आपत्ति दाखिल करने में आवेदन स्थापित किया जाता है, न्यायालय का पालन करके ऐसे डिक्री को रद्द करने की शक्ति है आदेश IX नियम 13 सीपीसी के तहत निर्धारित प्रक्रिया।

इसके अलावा, विवाद का बड़ा हिस्सा इसमें शामिल है अपील इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अंतर्गत आती है एस्सार कंस्ट्रक्शन बनाम एन.पी. राम कृष्ण रेड्डी [(2000) 6 एससीसी 94]। न्यायालय ने कहा कि क्योंकि सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की प्रयोज्यता, यदि न्यायालय ने किसी भी कारण से निर्णय नहीं सुनाया है, हालांकि आवेदन करने के लिए समय निर्धारित किया गया है समाप्त हो गया है और पुरस्कार को रद्द करने के लिए एक आवेदन है देरी को माफ करने की प्रार्थना के साथ न्यायालय से की गई जब तक आवेदन खारिज नहीं हो जाता तब तक फैसला नहीं सुना सकते। कोर्ट ने यह भी कहा कि डिक्री पारित होने के बाद भी धारा 17 के अंतर्गत, धारा 30 के अंतर्गत एक आवेदन किया जा सकता है पर्याप्त कारण स्थापित

होने पर मनोरंजन किया जाएगा। मैं किसी भी स्थिति में, आवेदन की अस्वीकृति होगी पुरस्कार रद्द करने से इनकार. ऐसे मामले में जहां ऐसा आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया जाता है कि इसमें देरी हो रही है और धर धारा 5 के तहत कोई पर्याप्त कारण नहीं बताया गया है लिमिटेशन एक्ट के तहत यह अपीलिय आदेश होगा अधिनियम की धारा 39(1)(vi)।

वर्तमान मामले में, 28 तारीख को डिक्री पारित करने से पहले अप्रैल 1997, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना की आपत्ति आवेदन हेतु निविदा हेतु समय बढ़ाने हेतु अधिनियम की धारा 30/33 के तहत। किसी गलती से वह अस्तित्व एक मौखिक प्रार्थना, जैसा कि फैसले में दर्ज किया गया था, को खारिज कर दिया गया था न्यायालय और डिक्री पारित किया गया. इसके बाद 5 मई को पुरस्कार को रद्द करने और माफ़ करने के लिए एक आवेदन आपत्तियां दाखिल करने में हुई देरी पर अधिवक्ता एस. भट्टाचार्य. उक्त आवेदन संलग्न था फरक्का के कार्यपालक अभियंता बिजोन कुमार घोषाल का हलफनामा बैराज परियोजना. विलम्ब क्षमा हेतु निर्देशित किया गया 17 तारीख को अधिशाषी अभियंता ने अधिवक्ता से संपर्क किया अप्रैल और उसे मसौदा तैयार करने के निर्देश दिए आवेदन पत्र। 18, 19 और 20 अप्रैल को कोर्ट थी क्रमशः शनिवार और रविवार को अवकाश होने के कारण बंद है। यह यह भी कहा गया कि अपीलकर्ता के वकील ने तैयारी शुरू कर दी है 22 अप्रैल को ड्राफ्ट जिसे 29 अप्रैल को अंतिम रूप दिया गया इसके बाद तल्लीनता, मोहर लगाई गई और 2 मई को तैयार कर दिया गया। इसे 5 मई को कोर्ट के सामने पेश किया गया था। वह आवेदन पत्र तैयार किया गया था और उस पर अधिवक्ता श्री एस. द्वारा हस्ताक्षर किये गये थे। भट्टाचार्य. इसके अलावा, अपीलकर्ता ने एक आवेदन दायर किया 16 मई को पारित फैसले और डिक्री को वापस लेने के लिए 1997 के अर्वाइड केस नंबर 22 में 28 अप्रैल। उस आवेदन में दाखिल करने में देरी को माफ़ करने के भी यही कारण हैं आवेदन का

उल्लेख किया गया था और प्रार्थना को याद करते हुए निर्णय और डिक्री और दाखिल करने की अनुमति देना पुरस्कार रद्द करने के लिए आवेदन किया गया था। मैं उस आवेदन का समर्थन पूरक शपथ पत्र था 19 मई को टेंडर किया गया।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि सीमा अवधि के भीतर, के कार्यकारी अभियंता विभाग ने 17 अप्रैल को वकील से संपर्क कर उन्हें जानकारी दी आपत्ति आवेदन दाखिल करने हेतु आवश्यक निर्देश पुरस्कार के खिलाफ. द्वारा इसे तैयार करने में देरी हुई विद्वान वकील. ऐसा प्रतीत होता है कि वही सलाह है दुर्भाग्य से मौखिक रूप से, अदालत से उस आपत्ति का अनुरोध किया आवेदन तैयार किया जा रहा था और उसके बाद इसे प्रस्तुत किया गया 5 मई को न्यायालय के समक्ष। उक्त कथन के अनुसार, यह है जाहिर है कि इसे तैयार करने और टेंडर देने में देरी हुई की ओर से न्यायालय के समक्ष आवेदन किया गया था संबंधित वकील. इसके लिए यह पर्याप्त कारण होगा क्षमा करते हुए, दाखिल करने में लगभग 12 से 13 दिन की देरी हुई आपत्तियाँ. एस्सार कंस्ट्रक्शन (सुप्रा) में, यह न्यायालय धारा 17 के तहत डिक्री पारित होने के बाद भी आयोजित किया जाता है, और धारा 30 के तहत आवेदन पर विचार किया जा सकता है बशर्ते पर्याप्त कारण स्थापित है. किसी भी स्थिति में आवेदन को अस्वीकार करने का अर्थ रद्द करने से इंकार करना होगा पुरस्कार। यह निर्णय तथ्यों पर लागू होगा वर्तमान मामले में और चूँकि इसके लिए पर्याप्त कारण थे देरी को माफ करते हुए, न्यायालय को इसे रद्द कर देना चाहिए था अवार्ड के आधार पर एक पक्षीय डिक्री पारित की गई।

इस स्तर पर, हम संदर्भ देने से पहले इसका उल्लेख करेंगे बड़ी बेंच से सवाल, डिवीजन बेंच में 16 दिसंबर 1998 के फैसले में कहा गया कि अधिनियम की धारा 33 के तहत दायर आवेदन, जो था पहले पुष्टि की गई थी, अपीलकर्ता ने क्षमादान की प्रार्थना की थी देरी की और धारा के तहत आवेदन दाखिल करने की अनुमति मांगी

33 उसमें बताई गई जमीन पर। न्यायालय ने यह अवलोकन किया की अनुमति मांगने में कुछ प्रक्रियात्मक त्रुटि थी न्यायालय आपत्तियां दाखिल करेगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होगी प्रार्थना की अस्वीकृति. न्यायालय ने यह भी माना कि वहाँ था इसमें कोई विवाद नहीं है कि मामले के कागजात उनके द्वारा सौंपे गए थे मसौदा तैयार करने के लिए अपीलकर्ता के वकील के प्रतिनिधि 17 अप्रैल 1997 को धारा 33 के तहत आवेदन सीमा अवधि की समाप्ति; उसके बाद मामला था आवेदन तक अपीलकर्ता के नियंत्रण से परे तैयार था; तैयारी और अंतिम रूप देने में परामर्श की देरी ड्राफ्ट का श्रेय अपीलकर्ता को नहीं दिया जा सकता; 29 अप्रैल को वरिष्ठ वकील द्वारा आवेदन का निपटारा किया गया 1997; इसके बाद इसे टाइप किया गया; 1 मई को छुट्टी थी और कोर्ट बंद था. आवेदन तदनुसार था 2 मई को पुष्टि की गई और इसलिए, देरी हुई है पर्याप्त रूप से समझाया गया है, खासकर तब जब अपीलकर्ता है सरकार। इसलिए, न्यायालय ने माना कि ऐसा होगा अपील की अनुमति दी और दाखिल करने में हुई देरी को माफ कर दिया धारा 33 के तहत आवेदन और परिणामस्वरूप अलग रखा गया डिक्री दिनांक 28 अप्रैल, 1987 लेकिन इसे ध्यान में रखते हुए आदेश की प्रयोज्यता के संबंध में मतभेद IX नियम 13 के तहत मामला बड़ी बेंच को भेजा गया। जैसा ऊपर कहा गया है, हमारे विचार में, डिवीजन बेंच सही थी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह एक उपयुक्त मामला था देरी को माफ करते हुए 28 तारीख के डिक्री को रद्द किया जाए अप्रैल 1987।

परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। दाखिल करने में देरी अधिनियम की धारा 30/33 के तहत आपत्ति आवेदन है क्षमा किया गया आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांक 07.10.1999 1998 के APOT No.858 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया और परिणामस्वरूप निर्णय और डिक्री दिनांक 28.4.1997 के अवार्ड केस

क्रमांक 22 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया 1997 को भी रद्द कर दिया गया है। कोई आदेश नहीं होगा लागत के रूप में।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित कि या गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं कि या जासकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।